- प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को तीन गुना करना।
- शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% तक करना।
- मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% तक करना।
- वैश्विक खाद्य व्यापार में साझेदारी को 1.5% से बढ़ाकर 3% तक करना।
- 2015 में फलों और सब्जियों के लिए प्रसंस्करण का स्तर 15% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- मंत्रिमंडल द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कृषि व्यवसाय और दृष्टिकोण, रणनीति एवं कार्य योजना को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत रणनीति को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

विजन दस्तावेज के आंकड़े

	2003-04 (बिलियन डॉलर)	2014-15 (बिलियन डॉलर)
कुल खाद्य उपभोग	205	
प्रसंस्कृत खाद्य	126	274
प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य	79	136
मूल्य संवर्धित खाद्य	48	138
खाद्य उत्पादों में मूल्य संवर्धित खाद्यों का हिस्सा	16%	50%

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जनसांख्यिकीय परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और तीव्र शहरीकरण के साथ सरकार के बढ़ते समर्थन के कारण तीव्र विकास के लिए तैयार है। ये कारक मूल्यवर्धित उत्पादों की मांग में वृद्धि करेंगे और इस प्रकार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं में सुधार होगा।

सरकार द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना, इस क्षेत्र में निवेश का समर्थन करने और अधिक FDI आकर्षित करने वाली नीतियों के निर्माण को सुनिश्चित करेगा। प्राकृतिक संसाधनों की व्यापक आपूर्ति और बढ़ते तकनीकी ज्ञान आधार के साथ भारत अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ की स्थिति में है। CII के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 10 वर्षों में 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को आकर्षित करने और 9 मिलियन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करने की क्षमता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र स्पष्ट रूप से निवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है और निवेशकों को महत्वपूर्ण विकास की संभावना प्रदान करता है।

10. सुझाव और आगे की राह (Suggestions and Way Forward)

वर्तमान समय में आउटपुट की गुणवत्ता एवं मूल्य में सुधार करने, प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए कच्चे माल की लागत को कम करने एवं किसानों की आय के स्तर में सुधार करने के लक्ष्य पर बल देते हुए उपर्युक्त चुनौतियों (tailbacks) से निपटने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

VISION IAS